

स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे हिमाचली भाषा व मास कम्युनिकेशन

छठी कक्षा से मिलेगी करियर काउंसलिंग

धर्मशाला, 24 जुलाई (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में शुक्रवार को शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और छात्र-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित की गई।

शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विषय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ कई दूरगामी सुझाव दिए।

बैठक के दौरान प्रदेश की स्थानीय भाषा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर विशेष बल दिया गया।

विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में हिमाचली भाषा से संबंधित एक विशेष अध्याय शामिल किया जाना चाहिए।

इसके अलावा विद्यार्थियों में संवाद कौशल, मीडिया साक्षरता और अभिव्यक्ति क्षमता को निखारने

के लिए पाठ्यक्रम में मास कम्युनिकेशन विषय को भी जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया।

छात्रों के सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए बैठक में स्कूल स्तर पर नियमित करियर काउंसलिंग और गाइडेंस शुरू करने पर जोर दिया गया। सुझाव दिया गया कि कक्षा 6वीं, 8वीं और 10वीं से ही विद्यार्थियों की रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षक उन्हें करियर को लेकर मार्गदर्शन प्रदान करें।

संघ ने न्यू शब्द हटाने की मांग रखी

शिमला, 24 जुलाई (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने एक ही कैडर में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्कूल प्रवक्ता और प्रवक्ता (स्कूल न्यू) जैसे 2 अलग-अलग पदनामों का विरोध किया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय नेगी ने इसे समान कार्य करने वाले शिक्षकों के साथ भेदभाव बताते हुए सरकार से वर्ष 2019 में जोड़े गए न्यू शब्द को हटाने की मांग की है। उनका कहना



धर्मशाला : शिक्षा सुधारों एवं विद्यार्थी हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर आयोजित बैठक के उपरान्त विषय विशेषज्ञ व स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा सामूहिक चित्र में। (ब्यूरो)

शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भविष्य उन्मुख व्यवस्था के लिए प्राप्त प्रत्येक रचनात्मक सुझाव का गंभीरता से अध्ययन करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों के अनुभव और नवाचारी विचार हमारी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, आधुनिक एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। - डॉ. राजेश शर्मा, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड

है कि सभी प्रवक्ताओं की शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा-शर्तें, वेतनमान और कार्य दायित्व समान हैं, इसलिए अलग-अलग पदनाम रखना तर्कसंगत नहीं है।

नई शिक्षा नीति-2020 के तहत सभी प्रवक्ता कक्षा छठी से 12वीं तक अध्यापन कर रहे हैं, ऐसे में एक ही

कैडर के लिए 2 नाम प्रशासनिक और संवैधानिक समानता के सिद्धांतों के विपरीत हैं।

यह मुद्दा कई बार सरकार व विभाग के समक्ष उठाया जा चुका है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। संघ ने सभी के लिए केवल स्कूल प्रवक्ता पदनाम लागू करने की मांग की है।

विषय विशेषज्ञों ने शिक्षा में सुधार के लिए दिए सुझाव



धर्मशाला में स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा के साथ विषय विशेषज्ञ • सौ. बोर्ड

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया। बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षा सुधारों, शिक्षा की गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन व विद्यार्थियों के समग्र विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। विषय विशेषज्ञ ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, छात्र केंद्रित व भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के सुझाव दिए। साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम में टांकरी, लिपि व भाषा से संबंधित अध्याय शामिल करने का सुझाव भी दिया। विद्यार्थियों में संवाद कौशल, मीडिया साक्षरता और अभिव्यक्ति क्षमता

विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में मास कम्युनिकेशन से जुड़े विषयों को शामिल करने पर भी चर्चा की गई।

बैठक में स्कूलस्तर पर विद्यार्थियों के लिए नियमित करियर काउंसिलिंग व करियर गाइडेंस आरंभ करने पर जोर दिया। विषय विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि छठी, आठवीं व दसवीं कक्षा से ही विद्यार्थियों का रुचि, योग्यता व भविष्य की संभावनाओं के आधार पर शिक्षकों की ओर से मार्गदर्शन किया जाएगा। डा. राजेश शर्मा ने कहा कि विषय विशेषज्ञों के सुझाव शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, नवाचारी और विद्यार्थी केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

प्रदेश के स्कूलों में टांकरी लिपि को पढ़ाने का सुझाव

अमर उजाला ब्यूरो

विषय विशेषज्ञों ने शिक्षा सुधारों और विद्यार्थी हित से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में टांकरी लिपि की पढ़ाई शुरू हो सकती है। इस लिपि को शुरू करने का सुझाव शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिया गया।

बैठक में विषय विशेषज्ञों, शिक्षा सुधारों और विद्यार्थी हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

विषय विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न

विषयों पर अपने विचार एवं सुझाव साझा किए। शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, छात्र केंद्रित एवं भविष्य उन्मुख बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की।

स्थानीय भाषाओं एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूली पाठ्यक्रम में हिमाचली भाषा (टांकरी लिपि/भाषा) से संबंधित एक अध्याय शामिल करने का सुझाव दिया गया।

शिक्षा सुधारों को लेकर विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षा बोर्ड में विचार-विमर्श

विद्यालयी पाठ्यक्रम में हिमाचली भाषा (टांकरी लिपि/भाषा) से संबंधित एक अध्याय शामिल करने का दिया सुझाव

पहली नजर ब्यूरो, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा की अध्यक्षता में आज शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षा सुधारों एवं विद्यार्थी हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर एक सार्थक विचार-विमर्श आयोजित किया गया। बैठक में विषय विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार एवं सुझाव साझा किए। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, छात्र-केंद्रित एवं भविष्य उन्मुख बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान हिमाचल की स्थानीय भाषाओं एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालयी पाठ्यक्रम में



कैरियर काउंसलिंग एवं कैरियर गाइडेंस को नियमित रूप से संचालित करने बल

बैठक में विद्यार्थियों के लिए विद्यालय स्तर पर कैरियर काउंसलिंग एवं कैरियर गाइडेंस को नियमित रूप से संचालित करने तथा कक्षा 6वीं, 8वीं एवं 10वीं से ही विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता एवं भविष्य की संभावनाओं के अनुरूप शिक्षकों द्वारा व्यवस्थित मार्गदर्शन प्रदान करने पर भी विशेष बल दिया गया।

सुझावों की सराहना

डॉ. राजेश शर्मा ने प्राप्त सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा भविष्य उन्मुख शिक्षा व्यवस्था के लिए प्राप्त प्रत्येक रचनात्मक सुझाव का गंभीरता से अध्ययन करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों के अनुभव एवं सुझाव शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, नवाचारी एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हिमाचली भाषा (टांकरी लिपि/भाषा) से संबंधित एक अध्याय शामिल करने का सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त

विद्यार्थियों में प्रभावी संवाद कौशल, मीडिया साक्षरता एवं अभिव्यक्ति क्षमता के विकास के लिए विद्यालयी पाठ्यक्रम में मास

कम्युनिकेशन (Mass Communication) से संबंधित विषयवस्तु को भी सम्मिलित करने का सुझाव रखा गया।

The Sunny Times

HPBOSE EXPLORES CURRICULUM REFORMS AND EARLY CAREER GUIDANCE IN DHARAMSHALA SUMMIT



Sunny Mahajan | Dharamshala

In a masterpiece of administrative productivity, the Himachal Pradesh Board of School Education recently gathered a room full of subject-matter experts at its Dharamshala headquarters to hold a deeply meaningful brain-storming session on the grand, evergreen topic of fixing education.

Presided over by Board Chairman Dr. Rajesh Sharma, the grand assembly tackled the formidable challenge of implementing the National Education Policy 2020 by doing what boards do best: suggesting new things to shove into the syllabus.

Top on the list of brilliant additions was a proposal to introduce ancient Takri script into school textbooks to preserve local heritage—because nothing says modern workforce readiness quite like teaching kids an obscure historical script.

Not stopping at ancient linguistics, the experts also threw in a pitch for Mass Communication lessons to help students build real-world communication and media literacy skills, seamlessly blending 14th-century scripts with 21st-century media hype in a single curriculum.

To round off the day, the committee discovered that children might benefit from knowing what to do with their lives, strongly urging schools to roll out regular career counseling starting as early as 6th grade so 11-year-olds can finally chart their path to corporate survival.

Chairman Dr. Sharma wrapped up the session by politely thanking everyone, promising that the board will seriously ponder every single creative suggestion, proving once again that while actual education reform takes decades, talking about it over tea takes about two hours.